



Exam Genius

India's No. 1 Platform for UPSC
| SSC | BANK RAILWAY Exam

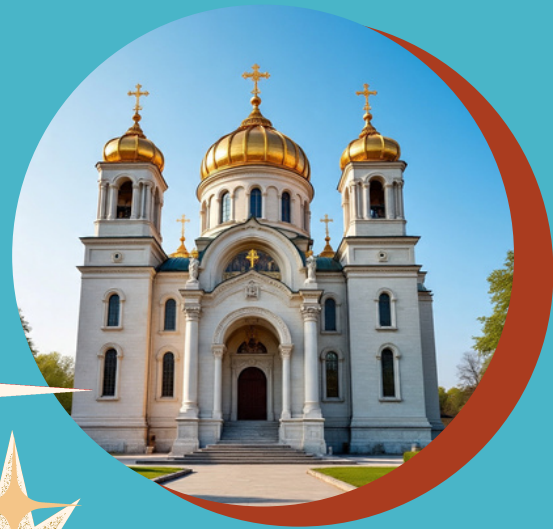


BANKING AND FINANCIAL AWARENESS

14 - 20 DEC 2025

3RD WEEK OF NOVEMBER

50+ MCQ
with detailed
explanation



- Banking & finance
- Banking Facilities
- Banking Appointment
- Banking Agreement



Ques: According to the ACI Worldwide 'Prime Time for Real-Time 2024' report, what share does UPI hold in global real-time payment transactions?
ACI Worldwide की 'Prime Time for Real-Time 2024' रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक रियल में लेनदेन पेमेंट टाइम-UPI की हिस्सेदारी कितनी है?

- A) 35%
- B) 49%
- C) 28%
- D) 56%
- E) 40%

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The International Monetary Fund (IMF), in its June 2025 report, recognised India's Unified Payments Interface (UPI) as the world's largest real-time retail fast-payment system by transaction volume.
- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने अपनी जून 2025 की रिपोर्ट में UPI को लेनदेन की मात्रा के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा रियलमाना। सिस्टम पेमेंट-फास्ट रिटेल टाइम-
- According to ACI Worldwide's 'Prime Time for Real-Time 2024' report, UPI accounts for 49% of global real-time payment transactions.
- ACI Worldwide की 'Prime Time for Real-Time 2024' रिपोर्ट के अनुसार, UPI वैश्विक रियल का लेनदेन पेमेंट टाइम-49% हिस्सा रखता है।
- India recorded 129.3 billion real-time transactions, the highest in the world, far ahead of countries like Brazil, Thailand, China and South Korea.
- भारत ने 129.3 बिलियन रियलकिए दर्ज लेनदेन टाइम-, जो ब्राज़ील, थाईलैंड, चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों से कहीं अधिक हैं।
- Government, RBI and NPCI initiatives such as BHIM-UPI incentives and Payment Infrastructure Development Fund (PIDF) support helped small merchants rapidly adopt digital payments.
- सरकार, RBI और NPCI की BHIM-UPI इंसेंटिव और पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (PIDF) जैसी पहलों ने छोटे व्यापारियों को डिजिटल भुगतान अपनाने में मदद की।
- As of 31 October 2025, 5.45 crore digital touchpoints and 56.86 crore QR codes were deployed across around 6.5 crore merchants nationwide.
- 31 अक्टूबर 2025 तक, देशभर में लगभग 6.5 करोड़ व्यापारियों के लिए 5.45 करोड़ डिजिटल टचपॉइंट और 56.86 करोड़ QR कोड तैनात किए गए थे।

Ques: Which company will acquire Rivpe Technology for ₹22 crore, resulting in 100% ownership on a fully diluted basis?

कौन कंपनी सी-₹22 करोड़ में Rivpe Technology का अधिग्रहण करेगी, जिससे पूर्ण रूप से डायल्यूटेड आधार पर 100% स्वामित्व प्राप्त होगा?

- A) Paytm / पेटीएम
- B) PhonePe / फोनपे
- C) Zagle Prepaid Ocean Services / जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज
- D) Razorpay / रेज़रपे
- E) BharatPe / भारतपे

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- Zagle Prepaid Ocean Services has announced the acquisition of Rivpe Technology for ₹22 crore.
- जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज ने ₹22 करोड़ में Rivpe Technology के अधिग्रहण की घोषणा की है।
- The acquisition includes 81,429 equity shares and 16,407 Compulsory Convertible Preference Shares (CCPS), resulting in 100% ownership on a fully diluted basis.
- इस अधिग्रहण में 81,429 इक्विटी शेयर और 16,407 अनिवार्य परिवर्तनीय वरीयता शेयर (CCPS) शामिल हैं, जिससे पूर्ण डायल्यूटेड आधार पर 100% स्वामित्व प्राप्त होगा।
- The deal is expected to be completed within 120 days.
- यह सौदा 120 दिनों के भीतर पूरा होने की संभावना है।
- In addition to the acquisition, Zagle will invest ₹75 crore in Rio.Money, the consumer payments brand of Rivpe.
- अधिग्रहण के अलावा, जैगल Rivpe के कंज़्यूमर पेमेंट ब्रांड Rio.Money में ₹75 करोड़ का अतिरिक्त निवेश करेगा।
- The investment will be used for product enhancement, technology upgrades, go-to-market initiatives, and expansion of consumer payment offerings.
- इस निवेश का उपयोग उत्पाद सुधार, तकनीकी उन्नयन, गो और रणनीतियों मार्केट-टू-जाएगा। किया लिए के विस्तार के सेवाओं भुगतान उपभोक्ता
- The total financial commitment by Zagle amounts to ₹97 crore, comprising

₹22 crore for the acquisition and ₹75 crore for Rio.Money's expansion.

• जैगल की कुल वित्तीय प्रतिबद्धता ₹97 करोड़ है, जिसमें ₹22 करोड़ अधिग्रहण और ₹75 करोड़ Rio.Money के विस्तार के लिए शामिल हैं।

Ques: AU Small Finance Bank has received approval to increase its foreign investment limit up to what level?

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को विदेशी निवेश सीमा बढ़ाकर कितनी करने की मंजूरी मिली है?

- A) 51%
- B) 60%
- C) 65%
- D) 70%
- E) 74%

Answer: Option E

Explanation / व्याख्या:

- AU Small Finance Bank has received approval from the Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance.
- एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (DFS) से मंजूरी प्राप्त हुई है।
- The approval allows the bank to increase its foreign investment limit from 49% to 74% of its paid-up capital.
- इस मंजूरी के तहत बैंक की चुकता पूंजी में विदेशी निवेश सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है।
- The 74% cap is the maximum permissible foreign investment limit for private sector banks in India.
- 74% की सीमा भारत में निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए अधिकतम अनुमेय विदेशी निवेश सीमा है।
- The move is expected to enhance capital availability, attract global investors and support the bank's growth plans.
- इस कदम से पूंजी उपलब्धता बढ़ेगी, वैश्विक निवेशकों की भागीदारी बढ़ेगी और बैंक की विकास योजनाओं को समर्थन मिलेगा।
- The approval is subject to compliance with RBI guidelines and applicable regulatory norms.

- यह मंजूरी RBI के दिशानिर्देशों और लागू नियामकीय नियमों के पालन के अधीन है।

Ques: Why did Airpay recently receive approval from the Reserve Bank of India (RBI)?

एयरपे को हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मंजूरी क्यों मिली है?

- A) To launch a digital bank / डिजिटल बैंक शुरू करने के लिए
- B) To operate as a cross-border payment aggregator / सीमा के एग्रीगेटर पेमेंट पार-लिए के करने कार्य में रूप
- C) To issue credit cards / क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए
- D) To manage government subsidies / सरकारी सब्सिडी प्रबंधन के लिए
- E) To provide cryptocurrency services / क्रिप्टोकॉरेसी सेवाएँ देने के लिए

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- Airpay Payment Services has received RBI approval to operate as a cross-border payment aggregator.
- एयरपे पेमेंट सर्विसेज को सीमा लिए के करने कार्य में रूप के एग्रीगेटर पेमेंट पार-RBI की मंजूरी मिली है।
- With this approval, Airpay has completed all required authorisations under the unified payment aggregator framework.
- इस मंजूरी के साथ, एयरपे ने यूनिफाइड पेमेंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के तहत सभी आवश्यक स्वीकृतियाँ पूरी कर ली हैं।
- Airpay is now licensed to operate as a payment aggregator across online, physical and cross-border payment categories.
- अब एयरपे ऑनलाइन, फिज़िकल और क्रॉस में रूप के एग्रीगेटर पेमेंट में श्रेणियों सभी बॉर्डर-सकेगा। कर कार्य
- The approval strengthens India's regulated fintech ecosystem and enables smoother international digital transactions.
- यह मंजूरी भारत के विनियमित फिनटेक इकोसिस्टम को मज़बूत बनाती है और अंतरराष्ट्रीय डिजिटल भुगतानों को आसान बनाती है।
- RBI's payment aggregator framework ensures compliance, transparency and consumer protection in digital payments.

- RBI का पेमेंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क डिजिटल भुगतानों में अनुपालन, पारदर्शिता और उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

Ques: Which bank launched the FIRST WOW! Black Credit Card backed by Fixed Deposit?

किस बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) से समर्थित FIRST WOW! ब्लैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया?

- A) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
- B) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
- C) IDFC First Bank / आईडीएफसी फर्स्ट बैंक
- D) Axis Bank / एक्सिस बैंक
- E) SBI Card / एसबीआई कार्ड

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- IDFC First Bank Limited launched the FIRST WOW! Black Credit Card, a premium credit card backed by a Fixed Deposit (FD).
- आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड ने FIRST WOW! ब्लैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, जो फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) से समर्थित एक प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है।
- The card offers 0% forex (FX) markup, making it attractive for international travellers and cross-border online shoppers.
- इस कार्ड में 0% विदेशी मुद्रा (FX) मार्कअप की सुविधा है, जो इसे अंतरराष्ट्रीय यात्रियों और क्रॉस है। बनाता आकर्षक लिए के खरीदारों ऑनलाइन बॉर्डर-
- Eligibility: Available to individuals aged 18 years and above, against a Fixed Deposit starting at Rs 20,000.
- पात्रता कार्ड यह :18 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, जिनके पास कम से कम ₹20,000 का फिक्स्ड डिपॉजिट हो।

About IDFC First Bank :

- Established : 2015
- HQ : Mumbai

- MD & CEO : V Vaidyanathan
- Tagline : Always You First

Ques: Which banks have received RBI approval to set up the Indian Digital Payment Intelligence Corporation (IDPIC)?

भारतीय डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन)IDPIC) की स्थापना के लिए RBI की मंजूरी किन बैंकों को मिली है?

- A) SBI and PNB / एसबीआई और पीएनबी
- B) Bank of Baroda and Canara Bank / बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक
- C) SBI and Bank of Baroda / एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा
- D) Union Bank and Bank of India / यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया
- E) SBI and HDFC Bank / एसबीआई और एचडीएफसी बैंक

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The State Bank of India (SBI) and Bank of Baroda (BoB) have received approval from the Reserve Bank of India (RBI).
- भारतीय स्टेट बैंक)SBI) और बैंक ऑफ बड़ौदा)BoB) को भारतीय रिज़र्व बैंक)RBI) से मंजूरी मिली है।
- The approval is for setting up a dedicated Digital Payments Intelligence Platform.
- यह मंजूरी एक समर्पित डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म की स्थापना के लिए दी गई है।
- The new entity will be named the Indian Digital Payment Intelligence Corporation (IDPIC).
- इस नई संस्था का नाम भारतीय डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन)IDPIC) होगा।
- IDPIC aims to strengthen fraud detection and prevention across public sector banks.
- IDPIC का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में धोखाधड़ी की पहचान और रोकथाम को मजबूत करना है।
- The proposed IDPIC will be incorporated as a Section 8 company under the Companies Act, 2013.
- प्रस्तावित IDPIC को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सेक्शन 8 कंपनी लाभकारी-गैर) पंज में रूप के (संस्थाीकृत किया जाएगा।

- RBI approval is subject to an exemption granted by the Department of Financial Services, Ministry of Finance.
- RBI की मंजूरी वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा दी गई छूट पर निर्भर है।
- The exemption allows the banks to hold more than 30% of the paid-up share capital in the company till 16 October 2026, under Section 19(2) of the Banking Regulation Act, 1949.
- यह छूट बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19(2) के तहत बैंकों को 16 अक्टूबर 2026 तक कंपनी की चुकता शेयर पूंजी का 30% से अधिक हिस्सा रखने की अनुमति देती है।

About Bank of Baroda :

- Established : 1908
- HQ : Vadodara, Gujarat
- MD & CEO : Debadatta Chand
- Tagline : India's International Bank

**Ques : What is ADB's revised GDP growth forecast for India for FY26?
FY26 के लिए ADB द्वारा भारत की संशोधित GDP वृद्धि दर कितनी है?**

- A) 6.5%
- B) 6.8%
- C) 7.0%
- D) 7.2%
- E) 7.5%

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- The Asian Development Bank (ADB) has raised India's GDP growth forecast for FY26 from 6.5% to 7.2%.
- एशियाई विकास बैंक (ADB) ने FY26 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 7.2% कर दिया है।
- The upward revision of 0.7 percentage points is mainly driven by strong domestic consumption supported by recent tax cuts.
- 0.7 प्रतिशत अंक का यह उन्नयन हालिया कर कटौती से समर्थित मजबूत घरेलू उपभोग के

कारण किया गया है।

- Stronger Q2 expansion reflected improving economic momentum in India, and the revision will also support Asia's overall growth, now projected at 5.1% for 2025.

- दूसरी तिमाही (Q2) में मजबूत विस्तार भारत की बेहतर आर्थिक गति को दर्शाता है, और इस संशोधन से एशिया की समग्र वृद्धि दर को भी बल मिलेगा, जिसे 2025 के लिए 5.1% अनुमानित किया गया है।

- The forecast was published in ADB's Asian Development Outlook, December 2025 edition.

- यह अनुमान ADB की Asian Development Outlook, दिसंबर 2025 रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया है।

Ques: According to the World Bank International Debt Report 2024, what was the debt situation of developing countries between 2022–2024?

वर्ल्ड बैंक के अंतरराष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट 2024 के अनुसार, 2022–2024 के बीच विकासशील देशों की ऋण स्थिति क्या थी?

A) Developing countries received more financing than debt service payments / विकासशील देशों ने ऋण सेवा भुगतानों से अधिक वित्तपोषण प्राप्त किया

B) Developing countries' debt service payments exceeded new financing by \$741 billion / विकासशील देशों के ऋण सेवा भुगतान नई वित्त पोषण से \$741 बिलियन अधिक थे

C) Debt gap was the lowest in 50 years / 50 वर्षों में ऋण अंतर सबसे कम था

D) Interest rates fell to pre-2020 levels / ब्याज दरें 2020 से पहले के स्तर पर गिर गईं

E) Bond markets were closed entirely / बॉन्ड बाजार पूरी तरह बंद थे

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- Developing countries paid \$741 billion more in debt service than they received in new financing between 2022–2024, marking the largest gap in 50 years.

- विकासशील देशों ने 2022–2024 के बीच नई वित्तपोषण की तुलना में \$741 बिलियन अधिक ऋण सेवा भुगतान किए, जो पिछले 50 वर्षों का सबसे बड़ा अंतर है।

- Despite high debt service, temporary relief came as interest rates peaked and bond markets reopened; \$90 billion of debt was restructured in 2024, the highest since 2010.
- उच्च ऋण सेवा के बावजूद, ब्याज दरें चरम पर पहुंचने और बॉन्ड बाजार के फिर से खुलने से अस्थायी राहत मिली; 2024 में \$90 बिलियन का ऋण पुनर्गठित किया गया, जो 2010 के बाद सबसे अधिक है।
- Bond investors provided \$80 billion in net financing, enabling new bond issuances but at high interest (~10%), double pre-2020 levels.
- बॉन्ड निवेशकों ने \$80 बिलियन शुद्ध वित्तपोषण प्रदान किया, जिससे नए बॉन्ड जारी किए गए लेकिन उच्च ब्याज (~10%) पर, जो 2020 से पहले के स्तर का दोगुना है।
- External debt of low- and middle-income countries reached \$8.9 trillion in 2024; IDA-eligible countries owe \$1.2 trillion (record).
- 2024 में निम्न और मध्यम आय वाले देशों का बाहरी ऋण \$8.9 ट्रिलियन पहुंच गया; IDA-योग्य देशों का ऋण \$1.2 ट्रिलियन है। (रिकॉर्ड)
- Developing nations paid \$415 billion in interest alone, diverting funds from health, education, and infrastructure; in highly indebted countries, 1 in 2 people cannot afford a minimum daily diet.
- विकासशील देशों ने केवल ब्याज पर \$415 बिलियन का भुगतान किया, जिससे स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के लिए धन हटा लिया गया; अत्यधिक ऋणी देशों में हर दो में एक व्यक्ति न्यूनतम दैनिक आहार भी नहीं खरीद सकता।
- Financing sources shifted: World Bank remained the largest low-cost financier, providing \$18.3 billion net financing + \$7.5 billion in grants in 2024.
- वित्तपोषण स्रोतों में बदलावरहा बना वित्तपोषक वाला लागत कम बड़ा सबसे बैंक वर्ल्ड ;, 2024 में \$18.3 बिलियन शुद्ध वित्तपोषण + \$7.5 बिलियन अनुदान प्रदान किए।
- Bilateral creditors withdrew funds (\$8.8 billion net repayments) instead of providing new loans; domestic debt grew faster than external debt in 86 countries.
- द्विपक्षीय ऋणदाता ने नई ऋण देने के बजाय \$8.8 बिलियन शुद्ध प्रतिपूर्ति ली; 86 देशों में घरेलू ऋण बाहरी ऋण की तुलना में तेजी से बढ़ा।

Ques : As per RBI data, how much loan amount has been written off by PSBs during the last five financial years and the current year till September 30, 2025?

RBI के अनुसार, पिछले पाँच वित्तीय वर्षों और 30 सितंबर 2025 तक चालू वर्ष में PSBs द्वारा कितना ऋण राइटहै गया किया ऑफ-?

A) ₹3,25,000 crore

- B) ₹4,80,000 crore
- C) ₹5,10,000 crore
- D) ₹6,15,647 crore
- E) ₹7,00,000 crore

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- RBI data shows that Public Sector Banks (PSBs) have written off loans worth ₹6,15,647 crore over the last five financial years and the current year up to September 30, 2025.
- RBI डेटा के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) ने पिछले पाँच वित्तीय वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष)30 सितंबर 2025 तकम (ें कुल ₹6,15,647 करोड़ के ऋण राइट हैं। किए ऑफ-
- Loan write-off is an accounting exercise to clean bank balance sheets and does not imply waiver of loans; banks continue recovery efforts even after write-off.
- ऋण राइट है प्रक्रिया लेखांकन एक ऑफ-, जिससे बैंक की बैलेंस शीट साफ की जाती है; इसका मतलब ऋण माफी नहीं होता। राइट प्रक्रिया की वसूली ऋण बैंक भी बाद के ऑफ- हैं। रखते रीजा
- Large write-offs are mainly related to stressed assets and non-performing assets (NPAs).
- बड़े राइट परिसंप तनावग्रस्त से रूप मुख्य ऑफ-त्तियों और एनपीए (Non-Performing Assets) से संबंधित होते हैं।

Ques : How much funding has the World Bank approved to promote clean air in Uttar Pradesh and Haryana?

उत्तर प्रदेश और हरियाणा में स्वच्छ वायु को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक ने कितनी राशि मंजूर की है?

- A) \$400 million
- B) \$500 million
- C) \$600 million
- D) \$700 million
- E) \$800 million

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The World Bank has approved \$600 million financing for two clean air programmes in Uttar Pradesh and Haryana.
 - विश्व बैंक ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा में दो स्वच्छ वायु कार्यक्रमों के लिए कुल \$600 मिलियन का वित्तपोषण स्वीकृत किया है।
 - The Uttar Pradesh Clean Air Management Programme (UPCAMP) will receive \$299.66 million to strengthen the state's Clean Air Plan through investments in transport, agriculture, and industrial sectors.
 - उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोग्राम (UPCAMP) को \$299.66 मिलियन दिए जाएंगे, जिससे परिवहन, कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश के माध्यम से राज्य की क्लीन एयर योजना को मजबूत किया जाएगा।
 - The Haryana Clean Air Project for Sustainable Development Operation will receive \$300 million and focuses on reducing air pollution through multi-sectoral interventions.
 - हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑपरेशन को \$300 मिलियन मिलेंगे, जो बहुहै। केंद्रित पर करने कम प्रदूषण वायु से माध्यम के हस्तक्षेपों क्षेत्रीय-
-

Ques: What is the main objective of the nationwide campaign “Aapki Poonji, Aapka Adhikar – Your Money, Your Right” launched by the Government of India?

“आपकी पूंजी, आपका अधिकार – योर मनी, योर राइट” अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है?

- A) Promoting digital payments / डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना
- B) Recovery of unclaimed financial assets / बिना दावे की वित्तीय परिसंपत्तियों की वापसी
- C) Financial literacy for students / छात्रों के लिए वित्तीय साक्षरता
- D) Tax compliance awareness / कर अनुपालन जागरूकता
- E) Expansion of banking services / बैंकिंग सेवाओं का विस्तार

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Ministry of Finance, Government of India conducted the nationwide campaign “Aapki Poonji, Aapka Adhikar – Your Money, Your Right” as a three-month drive from 4 October to 5 December 2025.
- वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने “आपकी पूंजी, आपका अधिकार – योर मनी, योर राइट” अभियान 4 अक्टूबर से 5 दिसंबर 2025 तक तीन महीने के राष्ट्रीय अभियान के रूप में चलाया।
- The campaign aims to facilitate the settlement and recovery of unclaimed financial assets such as bank deposits, insurance claims, dividends, shares, mutual funds and pension amounts.
- इस अभियान का उद्देश्य बैंक जमा, बीमा राशि, डिविडेंड, शेयर, म्यूचुअल फंड और पेंशन जैसी बिना दावे की वित्तीय परिसंपत्तियों की वापसी सुनिश्चित करना है।
- The initiative follows the 3A Framework – Awareness, Accessibility and Action.
- यह पहल 3A फ्रेमवर्क – जागरूकता, सुलभता और कार्रवाई – पर आधारित है।
- Key regulators involved include RBI, SEBI, IRDAI, PFRDA and IEPFA.
- इसमें RBI, SEBI, IRDAI, PFRDA और IEPFA जैसे प्रमुख नियामक शामिल हैं।
- District-level camps were organised in 477 districts across India during the campaign period.
- अभियान अवधि के दौरान देश के 477 जिलों में जिलागए। किए आयोजित शिविर स्तरीय-
- Digital platforms such as Unclaimed Deposits – Gateway to Access inforMation (UDGAM), Bima Bharosa and Mutual Fund Investment Tracing and Retrieval Assistant (MITRA) were used to trace and claim unclaimed assets.
- बिना दावे की परिसंपत्तियों की खोज और दावा करने के लिए UDGAM, बीमा भरोसा और MITRA जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया।
- In the first two months alone, nearly ₹2,000 crore of unclaimed funds were successfully reclaimed by rightful owners.
- केवल पहले दो महीनों में ही लगभग ₹2,000 करोड़ की बिना दावे की राशि सही मालिकों को वापस दिलाई गई।

Ques: Which company has launched the Wise Travel Card in India for multi-currency international travel?

भारत में बहु यात्रा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा-के लिए Wise Travel Card किस कंपनी ने लॉन्च किया है?

A) PayPal / पेपाल

- B) Wise / वाइज
- C) Revolut / रेवोल्यूट
- D) Mastercard / मास्टरकार्ड
- E) Visa / वीज़ा

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- Wise, a global money movement company, has launched its multi-currency Wise Travel Card in India.
 - वैश्विक मनी मूवमेंट कंपनी Wise ने भारत में अपना मल्टी करेंसी-Wise Travel Card लॉन्च किया है।
 - The card targets international travellers seeking transparent pricing and ease of use abroad.
 - यह कार्ड पारदर्शी मूल्य निर्धारण और विदेश में आसान उपयोग चाहने वाले यात्रियों को ध्यान में रखकर पेश किया गया है।
 - The launch was initially announced at the Global Fintech Festival (GFF) 2025.
 - इसकी घोषणा सबसे पहले ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल (GFF) 2025 में की गई थी।
 - GFF 2025 was held in Mumbai, Maharashtra.
 - GFF 2025 का आयोजन मुंबई, महाराष्ट्र में किया गया था।
 - The Wise Travel Card supports over 40 currencies, including Vietnam, Indonesia, Turkey and Georgia.
 - Wise Travel Card 40 से अधिक मुद्राओं को सपोर्ट करता है, जिनमें वियतनाम, इंडोनेशिया, तुर्की और जॉर्जिया शामिल हैं।
 - The card is accepted on the Visa Network in more than 160 countries worldwide.
 - यह कार्ड वीज़ा नेटवर्क पर 160 से अधिक देशों में स्वीकार्य है।
 - It offers free ATM withdrawals up to USD 200 per month, after which standard charges apply.
 - इसमें प्रति माह USD 200 तक निःशुल्क ATM निकासी की सुविधा है, इसके बाद मानक शुल्क लागू होंगे।
-

Ques: On which bank did the Reserve Bank of India impose a penalty of ₹99.30 lakh for regulatory non-compliance?

भारतीय रिज़र्व बैंक ने नियामकीय उल्लंघन के लिए ₹99.30 लाख का जुर्माना किस बैंक पर लगाया?

- A) Punjab & Sind Bank / पंजाब एंड सिंध बैंक
- B) Jammu and Kashmir Bank Limited / जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड
- C) Bank of Baroda / बैंक ऑफ बड़ौदा
- D) Union Bank of India / यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
- E) Central Bank of India / सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India imposed a monetary penalty of ₹99.30 lakh on Jammu and Kashmir Bank Limited.
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड पर ₹99.30 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।
- The penalty was imposed for contravention of Section 26A of the Banking Regulation Act, 1949.
- यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26A के उल्लंघन के लिए लगाया गया।
- The bank was also found non-compliant with RBI directions on the Internal Ombudsman Scheme, 2018.
- बैंक ने आंतरिक लोकपाल योजना, 2018 से संबंधित RBI के निर्देशों का पालन नहीं किया।
- Additional non-compliance was observed in Customer Service norms and Know Your Customer (KYC) guidelines.
- ग्राहक सेवा मानदंडों और 'अपने ग्राहक को जानें' (KYC) दिशानिर्देशों के पालन में भी कमी पाई गई।
- The penalty highlights RBI's focus on strengthening regulatory compliance and consumer protection in the banking sector.
- यह कार्रवाई बैंकिंग क्षेत्र में नियामकीय अनुपालन और उपभोक्ता संरक्षण को मज़बूत करने पर RBI के ज़ोर को दर्शाती है।

Ques: Which company has received a ₹12,000 crore loan from SBI and Bank of Baroda to fund its Dahej plant in Gujarat?

गुजरात के दहेज संयंत्र के लिए SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा से ₹12,000 करोड़ का ऋण किस कंपनी को मिला है?

- A) GAIL (India) Limited / गेल लिमिटेड (इंडिया)
- B) ONGC / ओएनजीसी
- C) Indian Oil Corporation / इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन
- D) Petronet LNG Limited / पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड
- E) Bharat Petroleum Corporation Limited / भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- Petronet LNG Limited has received a loan of ₹12,000 crore. The loan has been extended jointly by State Bank of India (SBI) and Bank of Baroda.
- पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड को ₹12,000 करोड़ का ऋण प्राप्त हुआ है। यह ऋण भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा संयुक्त रूप से दिया गया है।
- The funding will be used for the company's Dahej LNG plant in Gujarat.
- इस धनराशि का उपयोग गुजरात स्थित दहेज एलएनजी संयंत्र के लिए किया जाएगा।
- Petronet LNG is India's largest liquefied natural gas (LNG) importer.
- पेट्रोनेट एलएनजी भारत का सबसे बड़ा तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) आयातक है।
- The company is a joint venture of GAIL, ONGC, Indian Oil and Bharat Petroleum Corporation.
- यह कंपनी GAIL, ONGC, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का संयुक्त उपक्रम है।
- Each of these four public sector companies holds a 12.5% stake in Petronet LNG.
- इन चारों सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की पेट्रोनेट एलएनजी में 12.5% हिस्सेदारी है।

Ques: Which companies have partnered to offer insurance products to housing loan customers across 17 states and 340 districts in India?

भारत में 17 राज्यों और 340 जिलों में हाउसिंग लोन ग्राहकों को बीमा उत्पाद प्रदान करने के लिए कौन सी कंपनियों ने साझेदारी की है?

- A) HDFC Ergo and LIC / HDFC एर्गो और LIC
B) ICICI Lombard and Vastu Housing Finance / ICICI लोम्बार्ड और वासु हाउसिंग फाइनेंस
C) Bajaj Allianz and PNB Housing / बजाज एलियांज और PNB हाउसिंग
D) SBI General Insurance and L&T Finance / SBI जनरल इंश्योरेंस और L&T फाइनेंस
E) Tata AIG and Indiabulls / टाटा AIG और इंडियाबुल्स

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- ICICI Lombard General Insurance has partnered with Vastu Housing Finance to offer insurance to Vastu's housing loan customers.
- ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने वासु हाउसिंग फाइनेंस के हाउसिंग लोन ग्राहकों को बीमा प्रदान करने के लिए साझेदारी की है।
- The insurance coverage spans 17 states and 340 districts in India.
- बीमा कवरेज भारत के 17 राज्यों और 340 जिलों में उपलब्ध है।
- **Key insurance products offered:**
 - Income Protect: Covers 33 critical illnesses, accidental death, and permanent total disability.
 - इनकम प्रोटेक्ट :33 गंभीर बीमारियों, आकस्मिक मृत्यु और स्थायी पूर्ण विकलांगता को कवर करता है।
 - Home Insurance: Protects homes against fire, natural calamities, theft, and accidental damage.
 - होम इंश्योरेंस आग को घर ;, प्राकृतिक आपदाओं, चोरी और आकस्मिक क्षति से सुरक्षा प्रदान करता है।
 - Target segment includes peri-urban and rural borrowers, many of whom are first-generation homeowners and self-employed.
 - लक्षित वर्ग में उपहैं शामिल उधारकर्ता ग्रामीण और शहरी-, जिनमें से कई प्रथम पीढ़ी के गृहस्वामी और स्वरोजगार वाले हैं।
 - Distribution is through Vastu's branch network and digital platforms.
 - उत्पाद वासु की शाखा नेटवर्क और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वितरित किए जाते हैं।
 - Technology features include instant policy issuance via API integration and cashless claims within 60 minutes via IL TakeCare app.

- तकनीकी सुविधाओं में API इंटीग्रेशन के माध्यम से तुरंत पॉलिसी जारी करना और IL TakeCare ऐप के जरिए 60 मिनट में कैशलेस क्लेम शामिल हैं।

Ques: What has the RBI directed banks to do regarding core and non-core business risks?

RBI ने बैंक से कोर और गैर के जोखिमों के व्यवसाय कोर-संबंध में क्या करने को कहा है?

- A) Merge all lending entities / सभी लेंडिंग संस्थाओं को मिलाना
- B) Submit a plan to ringfence core business from riskier non-core business / कोर व्यवसाय को जोखिम भरे गैरकरना प्रस्तुत योजना का रखने अलग से व्यवसाय कोर-
- C) Stop overseas operations / विदेशी संचालन बंद करना
- D) Seek prior approval for all non-financial holdings / सभी गैर के होल्डिंग वित्तीय-लेना अनुमोदन पूर्व लिए
- E) Limit board approvals to one entity / बोर्ड अनुमोदन को एक संस्था तक सीमित करना

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- RBI has asked banks to submit a plan to ringfence core business from riskier non-core business by March 2026.
- RBI ने बैंक से मार्च 2026 तक कोर व्यवसाय को जोखिम भरे गैर अलग से व्यवसाय कोर- है। कहा को करने प्रस्तुत योजना का रखने
- Banks may have multiple lending entities but must obtain board approval.
- बैंक के पास कई लेंडिंग संस्थाएँ हो सकती हैं, लेकिन बोर्ड से अनुमोदन आवश्यक है।
- The new rules are to be implemented by March 31, 2028.
- नए नियम 31 मार्च 2028 तक लागू किए जाएंगे।
- This revises the October 2024 guidelines, which allowed only one entity per bank group for similar business.
- यह अक्टूबर 2024 के दिशानिर्देशों में संशोधन है, जो समान व्यवसाय के लिए प्रत्येक बैंक समूह में केवल एक संस्था की अनुमति देते थे।
- The change provides relief to banks, especially private banks with lending subsidiaries like HDFC Bank and Axis Bank.
- यह बदलाव बैंक, विशेषकर HDFC बैंक और Axis बैंक जैसी लेंडिंग सहायक कंपनियों वाले

निजी बैंकों के लिए राहत प्रदान करता है।

- For overseas operations, banks require an NOC from RBI for branches engaging in activities not permitted for the parent bank.
- विदेशी संचालन के लिए, उन शाखाओं को जो मूल बैंक के लिए अनुमत गतिविधियों में संलग्न नहीं हैं, RBI से NOC लेना आवश्यक है।
- RBI has relaxed rules for non-financial holding companies in businesses like mutual funds, insurance, pension fund management, investment advisory, and broking.
- RBI ने म्यूचुअल फंड, बीमा, पेंशन फंड प्रबंधन, निवेश परामर्श और ब्रोकिंग जैसे व्यवसायों में गैरनि लिए के कंपनियों होल्डिंग वित्तीय-यमों में ढील दी है।
- Now, non-financial holding companies can inform RBI within 15 days after board approval instead of seeking prior approval.
- अब गैर के अनुमोदन बोर्ड कंपनियां गहोलिंड वित्तीय-15 दिनों के भीतर RBI को सूचना दे सकती हैं, पहले की तरह पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

Ques: What change has the Reserve Bank of India (RBI) introduced regarding cash credit, current and overdraft accounts?

नकद ऋण (क्रेडिट कैश), करंट और ओवरड्राफ्ट खातों से संबंधित नियमों में RBI ने क्या बदलाव किया है?

- A) Complete ban on current accounts / करंट खातों पर पूर्ण प्रतिबंध
- B) Only one bank can maintain OD accounts / केवल एक बैंक OD खाते रख सकता है
- C) Easing of norms for opening and maintenance of CC, current and OD accounts / कैश क्रेडिट, करंट और ओवरड्राफ्ट खातों के खोलने व संचालन के नियमों में ढील
- D) Mandatory restrictions on cash credit accounts / कैश क्रेडिट खातों पर अनिवार्य प्रतिबंध
- E) Withdrawal of overdraft facilities / ओवरड्राफ्ट सुविधाओं की समाप्ति

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India has eased norms related to the opening and maintenance of cash credit, current and overdraft accounts.
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने कैश क्रेडिट, करंट और ओवरड्राफ्ट खातों के खोलने और संचालन से

जुड़े नियमों में ढील दी है।

- The changes were notified through amended master directions.
- ये बदलाव संशोधित मास्टर निर्देशों के माध्यम से जारी किए गए हैं।
- The regulator adopted these changes after considering industry feedback on draft rules issued on 1 October 2025.
- 1 अक्टूबर 2025 को जारी मसौदा नियमों पर उद्योग से मिले फीडबैक के बाद RBI ने ये बदलाव किए हैं।
- As per the final guidelines, banks can now offer cash credit accounts to customers based on their needs without any restrictions.
- अंतिम दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक अब ग्राहकों की आवश्यकता के आधार पर बिना किसी प्रतिबंध के कैश क्रेडिट खाते प्रदान कर सकते हैं।
- Banks may now maintain current accounts without restriction for customers with banking exposure below ₹100 million.
- ₹100 मिलियन से कम बैंकिंग एक्सपोज़र वाले ग्राहकों के लिए करंट अकाउंट पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।
- For exposures exceeding ₹100 million, banks with at least 10% exposure to the borrower can provide current and overdraft facilities.
- ₹100 मिलियन से अधिक एक्सपोज़र के मामलों में, जिन बैंकों का उधारकर्ता पर कम-से-कम 10% एक्सपोज़र है, वे करंट और ओवरड्राफ्ट सुविधाएं दे सकते हैं।
- If no bank or only one bank crosses the 10% exposure threshold, the top two lenders by exposure are allowed to maintain current and OD accounts.
- यदि कोई भी बैंक या केवल एक बैंक 10% एक्सपोज़र सीमा को पार करता है, तो RBI ने एक्सपोज़र के आधार पर शीर्ष दो उधारदाताओं को करंट और OD खाते रखने की अनुमति दी है।
- This modifies the earlier two-bank cap and aims to provide greater operational flexibility to borrowers and banks.
- यह पहले की दो में सीमा बैंक-संशोधन है और उधारकर्ताओं व बैंकों को अधिक परिचालन लचीलापन प्रदान करने का उद्देश्य रखता है।

Ques: Why has the RBI asked partner banks to stop issuing OneCard credit cards?

RBI ने पार्टनर बैंकों से OneCard क्रेडिट कार्ड जारी करना क्यों रोकने को कहा है?

- A) Due to high interest rates / उच्च ब्याज दरों के कारण
- B) Due to fraudulent transactions / धोखाधड़ी लेनदेन के कारण
- C) To seek clarity on data-sharing norms in the partnership / साझेदारी में डेटा-

कारण के मिलने न स्पष्टता पर नियमों के करने साझा

D) Because of low customer demand / कम ग्राहक मांग के कारण

E) Due to technical issues with card network / कार्ड नेटवर्क में तकनीकी समस्याओं के कारण

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- FPL Technologies offers co-branded credit cards under the brand OneCard.
 - FPL Technologies OneCard ब्रांड के तहत सहै। करता प्रदान कार्ड क्रेडिट ब्रांडेड-
 - RBI has asked partner banks to stop issuing OneCard credit cards.
 - RBI ने पार्टनर बैंकों से OneCard क्रेडिट कार्ड जारी करना रोकने को कहा है।
 - The reason is that RBI seeks clarity on the data-sharing norms followed in the partnership.
 - इसका कारण यह है कि RBI साझेदारी में अपनाए गए डेटा स्पष्टता पर नियमों साझाकरण- है। चाहता
 - The issuance ban will continue until RBI receives clarity or compliance confirmation.
 - यह कार्ड जारी करने पर रोक तब तक रहेगी जब तक RBI को स्पष्टता या अनुपालन की पुष्टि नहीं मिलती।
 - The action affects both FPL Technologies and its partner banks who issue the cards on its behalf.
 - यह कदम FPL Technologies और उसके पार्टनर बैंकों दोनों को प्रभावित करता है, जो कार्ड उसके behalf पर जारी करते हैं।
 - The move is seen as a regulatory hurdle impacting business operations.
 - इसे व्यवसायिक संचालन पर प्रभाव डालने वाली नियामक बाधा के रूप में देखा जा रहा है।
-

Ques: Which two institutions signed an MoU to expand access to mutual fund services across India?

भारत में म्यूचुअल फंड सेवाओं की पहुँच बढ़ाने के लिए किन दो संस्थानों ने समझौता (MoU) किया है?

- A) Department of Posts and BSE / डाक विभाग और बीएसई
- B) Department of Posts and NSE / डाक विभाग और एनएसई
- C) RBI and BSE / आरबीआई और बीएसई
- D) SEBI and India Post / सेबी और इंडिया पोस्ट
- E) LIC and BSE / एलआईसी और बीएसई

Answer: Option A

Explanation / व्याख्या:

- The Department of Posts (DoP) and BSE, Asia's oldest stock exchange, have signed a landmark MoU to expand access to mutual fund services across India.
- डाक विभाग (DoP) और एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज बीएसई ने भारत भर में म्यूचुअल फंड सेवाओं की पहुँच बढ़ाने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया है।
- The initiative will leverage India Post's extensive end-to-end presence in rural and semi-urban areas.
- इस पहल में ग्रामीण और अर्ध का उपस्थिति नेटवर्क व्यापक की पोस्ट इंडिया में क्षेत्रों शहरी-उपयोग किया जाएगा।
- The aim is to bring investment opportunities closer to millions of citizens with limited access to formal financial products.
- इसका उद्देश्य औपचारिक वित्तीय उत्पादों तक सीमित पहुँच रखने वाले करोड़ों नागरिकों तक निवेश के अवसर पहुँचाना है।
- Mutual fund distribution will be carried out through BSE StAR MF, India's largest mutual fund platform.
- म्यूचुअल फंड का वितरण भारत के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म बीएसई स्टार एमएफ (BSE StAR MF) के माध्यम से किया जाएगा।
- The MoU is valid for a period of three years, from 12 December 2025 to 11 December 2028.
- यह समझौता 12 दिसंबर 2025 से 11 दिसंबर 2028 तक, कुल तीन वर्षों के लिए वैध है।

About BSE :

- Established : 1875
- HQ : Mumbai
- Chairman : Subhasis Chaudhuri
- MD & CEO : Sundararaman Ramamurthy

Ques: Which institution announced that retail Central Bank Digital Currency (CBDC) transactions have crossed 120 million in India?

भारत में रिटेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) लेनदेन 120 मिलियन से अधिक होने की घोषणा किस संस्था ने की?

- A) Ministry of Finance / वित्त मंत्रालय
- B) State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक
- C) Securities and Exchange Board of India / भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड
- D) NITI Aayog / नीति आयोग
- E) Reserve Bank of India / भारतीय रिज़र्व बैंक

Answer: Option E

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) announced that the volume of retail Central Bank Digital Currency (CBDC) transactions has crossed 120 million.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने घोषणा की है कि रिटेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) लेनदेन की संख्या 120 मिलियन से अधिक हो गई है।
- The total transaction value through retail CBDC has exceeded ₹28,000 crore.
- रिटेल CBDC के माध्यम से कुल लेनदेन मूल्य ₹28,000 करोड़ से अधिक हो गया है।
- More than 8 million users are actively using the digital rupee (e₹) for daily transactions.
- 80 लाख से अधिक उपयोगकर्ता दैनिक लेनदेन के लिए डिजिटल रुपया (e₹) सक्रिय रूप से उपयोग कर रहे हैं।
- Retail CBDC, also known as the digital rupee (e₹), is RBI's flagship digital payment initiative providing a sovereign, secure, and efficient alternative to cash.
- रिटेल CBDC, जिसे डिजिटल रुपया (e₹) भी कहा जाता है, RBI की प्रमुख डिजिटल भुगतान पहल है, जो नकद का संप्रभु, सुरक्षित और कुशल विकल्प प्रदान करती है।
- The pilot project for retail CBDC began on 1 December 2022 and has since seen significant growth in adoption.
- रिटेल CBDC का पायलट प्रोजेक्ट 1 दिसंबर 2022 को शुरू हुआ था, जिसके बाद इसके उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- RBI is also exploring programmable CBDCs for use in government schemes, Direct Benefit Transfers (DBTs), and sector-specific applications like education and healthcare.

- RBI प्रोग्रामेबल CBDC की संभावनाएँ भी तलाश रहा है, जिनका उपयोग सरकारी योजनाओं, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) और शिक्षा व स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में किया जा सकता है।
- To promote innovation, RBI has established a retail CBDC sandbox allowing banks and fintech firms to test CBDC-based wallets and payment solutions.
- नवाचार को बढ़ावा देने के लिए RBI ने रिटेल CBDC सैंडबॉक्स स्थापित किया है, जिससे बैंक और फिनटेक कंपनियाँ CBDC-आधारित वॉलेट और भुगतान समाधान विकसित व परीक्षण कर सकें।

Ques: Which public sector bank partnered with the Government of Nagaland for the Hornbill Festival 2025?

हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए नागालैंड सरकार के साथ किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने साझेदारी की?

- A) Bank of Baroda / बैंक ऑफ बड़ौदा
- B) Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक
- C) State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक
- D) Canara Bank / केनरा बैंक
- E) Union Bank of India / यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

Answer: Option A

Explanation / व्याख्या:

- Bank of Baroda, a public sector bank, partnered with the Government of Nagaland for the Hornbill Festival 2025.
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा ने हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए नागालैंड सरकार के साथ साझेदारी की।
- The festival was held at the Kisama Heritage Village near Kohima.
- यह महोत्सव कोहिमा के पास किसामा हेरिटेज विलेज में आयोजित किया गया।
- Bank of Baroda has strengthened its presence in North East India with 3 Regional Offices and 197 branches.
- बैंक ऑफ बड़ौदा ने पूर्वोत्तर भारत में 3 क्षेत्रीय कार्यालयों और 197 शाखाओं के साथ अपनी उपस्थिति मजबूत की है।
- About 61% of the bank's branches in the region are located in rural and semi-urban areas.

- क्षेत्र में बैंक की लगभग 61% शाखाएँ ग्रामीण और अर्धहैं। स्थित में क्षेत्रों शहरी-
- The bank recently inaugurated a new Zonal Office in Guwahati to cover all North Eastern States.
- बैंक ने सभी पूर्वोत्तर राज्यों को कवर करने के लिए हाल ही में गुवाहाटी में एक नया ज़ोनल कार्यालय शुरू किया है।

Ques: What was India's Wholesale Price Inflation (WPI) rate in November 2025?

नवंबर 2025 में भारत की थोक मूल्य मुद्रास्फीति) WPI) दर कितनी रही?

- A) 0.52
- B) 0.13%
- C) -0.32%
- D) -1.21%
- E) 2.16%

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- Wholesale Price Inflation (WPI) in India stood at -0.32% in November 2025, according to government data.
- सरकारी आंकड़ों के अनुसार, नवंबर 2025 में भारत की थोक मूल्य मुद्रास्फीति) WPI) - 0.32% रही।
- The marginal improvement was driven by a month-on-month increase in prices of food articles such as pulses and vegetables.
- यह मामूली सुधार दालों और सब्जियों जैसी खाद्य वस्तुओं की मासिक आधार पर बढ़ती कीमतों के कारण हुआ।
- WPI-based inflation was recorded at -1.21% in October 2025.
- अक्टूबर 2025 में WPI आधारित मुद्रास्फीति -1.21% थी।
- In comparison, WPI inflation was 2.16% in November last year.
- तुलना में, पिछले वर्ष नवंबर में WPI मुद्रास्फीति 2.16% थी।

Recent WPI-based Retail inflation in India:

- October 2025 : -1.21%

- September 2025 : 0.13%
- August 2025 : 0.52%
- July 2025 : - 0.58%

Ques: Which city's metro rail expansion has received a USD 240 million loan from the Asian Development Bank (ADB)?

एशियाई विकास बैंक) ADB) से 240 मिलियन डॉलर का ऋण किस शहर के मेट्रो विस्तार के लिए मिला है?

- A) Bengaluru / बेंगलुरु
- B) Hyderabad / हैदराबाद
- C) Chennai / चेन्नई
- D) Mumbai / मुंबई
- E) Kolkata / कोलकाता

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The Asian Development Bank (ADB) has approved a USD 240 million loan for the expansion of the Chennai Metro Rail network.
 - एशियाई विकास बैंक) ADB) ने चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए 240 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है।
 - This is the second tranche under the Chennai Metro Rail Investment Project.
 - यह चेन्नई मेट्रो रेल निवेश परियोजना के तहत दूसरी किस्त है।
 - The project aims to provide cleaner, safer, and more reliable urban transport across the Chennai Metropolitan Area.
 - इस परियोजना का उद्देश्य चेन्नई महानगरीय क्षेत्र में स्वच्छ, सुरक्षित और अधिक भरोसेमंद शहरी परिवहन उपलब्ध कराना है।
 - The loan is part of ADB's USD 780 million multi-tranche financing facility approved in 2022. The first tranche of USD 350 million was approved earlier.
 - यह ऋण 2022 में स्वीकृत ADB की 780 मिलियन डॉलर की मल्टी-ट्रान्च फाइनेंसिंग सुविधा का हिस्सा है, जिसमें पहले 350 मिलियन डॉलर की पहली किस्त स्वीकृत की गई थी।
-

Ques: NABARD has extended a loan of ₹1,685.27 crore to which organisation?

नाबार्ड ने ₹1,685.27 करोड़ का ऋण किस संस्था को प्रदान किया है?

- A) Odisha Power Generation Corporation / ओडिशा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन
- B) Odisha Power Transmission Corporation Limited / ओडिशा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
- C) GRIDCO Limited / ग्रिडको लिमिटेड
- D) Odisha Hydro Power Corporation / ओडिशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन
- E) Power Finance Corporation / पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) has sanctioned a loan of ₹1,685.27 crore to Odisha Power Transmission Corporation Limited (OPTCL).
- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कॉर्पोरेशन ट्रांसमिशन पावर ओडिशा ने (नाबार्ड) लिमिटेड (OPTCL) को ₹1,685.27 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया है।
- The loan carries an interest rate of 7.75% per annum.
- इस ऋण पर वार्षिक ब्याज दर 7.75% निर्धारित की गई है।
- The tenure of the loan is 15 years, with the first 3 years as a moratorium period.
- ऋण की अवधि 15 वर्ष है, जिसमें पहले 3 वर्ष मोराटोरियम अवधि के रूप में रखे गए हैं।
- The funding will support power transmission infrastructure development in Odisha.
- यह वित्तपोषण ओडिशा में विद्युत पारेषण अवसंरचना के विकास में सहायता करेगा।

About NABARD :

- Established : 12 July 1982 (Under recommendations of B. Sivaraman Committee)
- HQ : Mumbai
- Chairman : K V Shaji

Ques: Why has RBI directed banks to link MSME loans to an external benchmark?

RBI ने MSME ऋणों को बाहरी बेंचमार्क से जोड़ने का निर्देश क्यों दिया है?

- A) To increase bank profitability / बैंकों की लाभप्रदता बढ़ाने के लिए
- B) To standardise MSME loan documentation / MSME ऋण दस्तावेज़ों का मानकीकरण करने के लिए
- C) To improve monetary policy transmission / मौद्रिक नीति के प्रभावी प्रसारण के लिए
- D) To reduce MSME loan defaults / MSME ऋण डिफॉल्ट कम करने के लिए
- E) To eliminate collateral requirements / जमानत की आवश्यकता समाप्त करने के लिए

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- RBI has directed banks to link MSME loans to an external benchmark to ensure faster and transparent transmission of policy rate changes to borrowers.
- RBI ने MSME ऋणों को बाहरी बेंचमार्क से जोड़ने का निर्देश इसलिए दिया है ताकि नीतिगत दरों में बदलाव का प्रभाव उधारकर्ताओं तक तेज़ी और पारदर्शिता के साथ पहुंच सके।
- Under this system, the interest rate reset period for MSME loans has been reduced to three months.
- इस प्रणाली के तहत MSME ऋणों के लिए ब्याज दर रीसेट अवधि तीन महीने कर दी गई है।
- Existing MSME borrowers are allowed to switch to the external benchmark-linked interest rate regime as per mutually agreed terms with banks.
- मौजूदा MSME उधारकर्ताओं को बैंक के साथ पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों के अनुसार बाहरी बेंचमार्क आधारित ब्याज दर प्रणाली में स्थानांतरित होने की अनुमति दी गई है।

Ques: India's banking sector recently achieved a 20-year low in Gross Non-Performing Assets (GNPAs). What was the GNPA level by March 2025?

भारत के बैंकिंग क्षेत्र में मार्च 2025 तक सकल गैर) परिसंपत्तियाँ निष्पादित-GNPA) किस स्तर तक आ गईं?

- A) 3.95%
- B) 2.98%
- C) 2.58%
- D) 2.31%
- E) 1.85%

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- India's banking sector recorded its lowest Gross Non-Performing Assets (GNPA) level in 20 years, declining from 11.46% in 2018 to 2.31% by March 2025.
- भारत के बैंकिंग क्षेत्र में सकल गैर परिसंपत्तियाँ निष्पादित-2018 में 11.46% से घटकर मार्च 2025 में 2.31% पर आ गई, जो 20 वर्षों में सबसे कम स्तर है।
- Net NPA (NNPA) ratio also fell sharply to 0.52%, the lowest in two decades, compared to 6.1% in 2018, supported by stronger provisioning.
- शुद्ध एनपीए अनुपात भी 2018 के 6.1% से घटकर 0.52% पर आ गया, जो दो दशकों में सबसे कम है।
- GNPA of Public Sector Banks (PSBs) declined from 9.11% in March 2021 to 2.58% in March 2025.
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के GNPA मार्च 2021 में 9.11% से घटकर मार्च 2025 में 2.58% रह गए।
- GNPA of Scheduled Commercial Banks (SCBs) reduced from 7.33% to 2.22% during the same period.
- इसी अवधि में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के GNPA 7.33% से घटकर 2.22% हो गए।
- Domestic deposits rose from ₹88.35 lakh crore (2015) to ₹231.90 lakh crore (2025), while credit expanded from ₹66.91 lakh crore to ₹181.34 lakh crore.
- घरेलू जमा 2015 में ₹88.35 लाख करोड़ से बढ़कर 2025 में ₹231.90 लाख करोड़ हो गए, जबकि ऋण ₹66.91 लाख करोड़ से बढ़कर ₹181.34 लाख करोड़ हो गया।
- Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) improved from 12.94% (March 2015) to 17.36% (March 2025).
- पूंजी से जोखिमका परिसंपत्तियों भारित- अनुपात (CRAR) मार्च 2015 के 12.94% से बढ़कर मार्च 2025 में 17.36% हो गया।
- Total business of PSBs increased from ₹203 lakh crore (FY23) to ₹252 lakh crore (FY25), with net profit rising from ₹1.05 lakh crore to ₹1.78 lakh crore.
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कुल व्यवसाय FY23 में ₹203 लाख करोड़ से बढ़कर FY25 में

₹252 लाख करोड़ हो गया और शुद्ध लाभ ₹1.05 लाख करोड़ से बढ़कर ₹1.78 लाख करोड़ हो गया।

- Scheduled Commercial Banks recorded their highest-ever aggregate net profit of ₹4.01 lakh crore in FY25.
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने FY25 में अब तक का सबसे अधिक कुल शुद्ध लाभ ₹4.01 लाख करोड़ दर्ज किया।

**Ques: What is SBI's user target under YONO 2.0 over the next two years?
YONO 2.0 के तहत अगले दो वर्षों में SBI का यूजर लक्ष्य क्या है?**

- A) 150 million
- B) 175 million
- C) 180 million
- D) 200 million
- E) 250 million

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- State Bank of India (SBI) has launched YONO 2.0, the upgraded version of its digital banking platform "You Only Need One (YONO)".
- भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म "यू ओनली नीड वन (YONO)" का उन्नत संस्करण YONO 2.0 लॉन्च किया है।
- SBI aims to double its YONO user base from 96 million to 200 million in the next two years.
- SBI का लक्ष्य अगले दो वर्षों में YONO यूजर्स की संख्या 96 मिलियन से बढ़ाकर 200 मिलियन करना है।
- SBI plans to hire around 10,000 staff (floor managers) to shift customers from branches to digital channels.
- SBI शाखाओं से ग्राहकों को डिजिटल चैनलों पर स्थानांतरित करने के लिए लगभग 10,000 कर्मचारियों (फ्लोर मैनेजर) की नियुक्ति करेगा।
- YONO 2.0 is expected to reduce customer service costs by 40–60 percent.
- YONO 2.0 से ग्राहक सेवा लागत में 40–60 प्रतिशत तक कमी आने की उम्मीद है।
- The platform will help reduce branch footfall by 20–30 percent and enhance productivity.

- यह प्लेटफॉर्म शाखाओं में भीड़ को 20–30 प्रतिशत तक कम करेगा और उत्पादकता बढ़ाएगा।
- YONO 2.0 will accelerate digital credit delivery through automated decision-making processes.
- YONO 2.0 ऑटोमेटेड निर्णय प्रणाली के माध्यम से डिजिटल क्रेडिट को तेज करेगा।
- Currently, YONO 2.0 is available in English and Hindi and will soon support 15 languages.
- YONO 2.0 फिलहाल अंग्रेज़ी और हिंदी में उपलब्ध है और जल्द ही 15 भाषाओं में उपलब्ध होगा।

